



बजट के बाद 'कृषि और सहकारिता' पर हुए वेबिनार में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 24 FEB 2023 12:20PM by PIB Delhi

आप सभी का बजट से जुड़े इस महत्वपूर्ण webinar में स्वागत है। पिछले 8-9 वर्षों की तरह, इस बार भी बजट में कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों से बजट के अगले दिन के अखबार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर बजट को गांव, गरीब और किसान वाला बजट' कहा गया है। 2014 में कृषि बजट 25 हजार करोड़ रुपए से भी कम था, हमारे आने से पहले। आज देश का कृषि बजट बढ़कर 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है।

साथियों,

आजादी के बाद लंबे समय तक हमारा कृषि क्षेत्र अभाव के दबाव में रहा। हम अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए दुनिया पर निर्भर थे। लेकिन हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मिनिर्भर बनाया बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए हैं। आज भारत कई तरह के कृषि उत्पादों को निर्यात कर रहा है। हमने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक किसानों की पहुंच को आसान बनाया है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बात चाहे आत्मिनिर्भरता की हो या निर्यात की, हमारा लक्ष्य सिर्फ चावल, गेहूं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, 2021-22 में दलहन के आयात पर 17 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। Value added food products के आयात पर 25 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। इसी तरह 2021-22 में खाद्य तेलों के आयात पर डेढ़ लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। सिर्फ इतनी ही चीजों के आयात पर करीब 2 लाख करोड़ रुपये खर्च हो गए, मतलब इतना पैसा देश के बाहर चला गया। ये पैसा हमारे किसानों के पास पहुंच सकता है, अगर हम इन कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भी आत्मिनिर्भर बन जाएं। पिछले कुछ वर्षों से लगातार बजट में इन सेक्टर्स को आगे बढ़ाने वाले फैसले किए जा रहे हैं। हमने MSP में बढ़ोतरी की, दलहन उत्पादन को बढ़ावा दिया, फूड प्रोसेसिंग करने वाले फूड पार्कों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही खाद्य तेल के मामले में पूरी तरह आत्मिनिर्भर होने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है।

साथियों.

जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों को दूर नहीं कर लेते, संपूर्ण विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता। आज भारत के कई सेक्टर्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे ऊर्जावान युवा बढ़-चढ़कर उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में उनकी भागीदारी कम है, जबिक वो भी इसके महत्व और इसमें आगे बढ़ने की संभावनाओं के बारे में जानते हैं। प्राइवेट इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर से दूरी बनाए हुए हैं। इस खाली जगह को भरने के लिए इस साल के बजट में कई तरह के ऐलान किए गए हैं। उदाहरण के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में ओपन सोर्स बेस्ड प्लेटफॉर्म को बढ़ावा। हमने digital public infrastructure को ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म की तरह सामने रखा है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे UPI का ओपन प्लेटफॉर्म, जिसके जिए आज डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। आज जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति हो रही है, उसी तरह एग्री-टेक डोमेन में भी इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की अपार संभावनाएं बन रही हैं। इसमें संभावना है लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने की, इसमें अवसर है बड़े बाजार तक पहुंच को आसान बनाने का, इसमें मौका है टेक्नोलॉजी के जिए drip irrigation को बढ़ावा देने का, साथ ही सही सलाह, सही व्यक्ति तक समय से पहुंचाने की दिशा में हमारे युवा काम कर सकते हैं। जिस तरह से मेडिकल सेक्टर में लेब काम करते हैं उसी तरह से निजी soil testing labs स्थापित किये जा सकते हैं। हमारे युवा अपने इनोवेशन से सरकार और किसान के बीच सूचना के सेतु बन सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि कौन सी फसल ज्यादा मुनाफा दे सकती है। वो फसल के बारे में अनुमान लगाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पॉलिसी मेकिंग में मदद कर सकते हैं। किसी

जगह पर मौसम में आ रहे बदलावों की real time information भी उपलब्ध करा सकते हैं। यानी हमारे युवाओं के लिए इस सेक्टर में करने के लिए बहुत कुछ है। इसमें सक्रिय भागीदारी करके वो किसानों की मदद करेंगे, साथ ही उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

साथियों,

इस बार के बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। एग्री-टेक स्टार्टअप्स के लिए एक्सेलेरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। इसलिए, हम सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे, बल्कि हम आपके लिए funding avenues भी तैयार कर रहे हैं। तो अब हमारे युवा entrepreneurs की बारी है, वो उत्साह से आगे बढ़ें और लक्ष्य हासिल करके दिखाएं। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि 9 वर्ष पहले देश में एग्री स्टार्टअप नहीं के बराबर थे, लेकिन आज ये तीन हजार से भी ज्यादा हैं। फिर भी हमें और तेज रफ्तार से आगे बढ़ना होगा।

साथियों.

आप सब जानते हैं कि भारत की पहल पर इस साल को International Year of Millets घोषित किया गया है। मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने का मतलब है कि हमारे छोटे किसानों के लिए ग्लोबल मार्केट तैयार हो रहा है। मोटे अनाज को अब देश ने इस बजट में ही 'श्रीअन्न' की पहचान दी है। आज जिस तरह श्रीअन्न को प्रमोट किया जा रहा है, उससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इस क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप्स के प्रोथ की संभावना भी बढ़ी है, जो ग्लोबल मार्केट तक किसानों की पहुंच को आसान बनाए।

साथियों.

भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया revolution हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है। लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में cooperative sector को टैक्स सम्बन्धी राहतें दी गयी है जो काफी महत्वपूर्ण हैं। मैनुफ़ैक्चिरंग करने वाली नई सहकारी सिमितियों को कम टैक्स रेट का फायदा मिलेगा। सहकारी सिमितियों द्वारा 3 करोड़ रुपए तक की नगद निकासी पर टीडीएस नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव सेक्टर के मन में हमेशा से एक भाव रहा है कि बाकी कंपनियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस बजट में इस अन्याय को भी खत्म किया गया है। एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 2016-17 के पहले किए गए पेमेंट पर टैक्स छूट दी गई है। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10 हजार करोड़ का फायदा होगा।

साथियों.

जिन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाएं पहले से नहीं हैं, वहां डेयरी और फिशरीज से जुड़ी सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को बहुत लाभ होगा। विशेषकर, फिशरीज़ में हमारे किसानों के लिए कई बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। पिछले 8-9 वर्षों में देश में मत्स्य उत्पादन करीब 70 लाख मीट्रिक टन बढ़ा है। 2014 के पहले, इतना ही उत्पादन बढ़ने में करीब-करीब तीस साल लग गए थे। इस बजट में पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 6 हज़ार करोड़ की लागत से एक नए सब-कंपोनेंट की घोषणा की गई है। इससे Fisheries Value Chain के साथ-साथ market को बढ़ावा मिलेगा। इससे मछुआरों और छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर बनेंगे।

साथियों.

हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और केमिकल आधारित खेती को कम करने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम प्रणाम योजना और गोबरधन योजना से इस दिशा में बड़ी मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूँ, हम सब एक टीम के रूप में इन सभी विषयों को आगे बढ़ाएँगे। मैं फिर एक बार आज के वेबिनार के लिए आपको शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे विश्वास है की आप सब स्टेकहोल्डर्स मिलकर के इस बजट का अधिकतम लाभ अधिकतम लोगों को जल्दी से जल्दी कैसे मिले, बजट में किये प्रावधानों और आपकी शक्ति आपका संकल्प जुड़ जाये। मुझे पक्का विश्वास है की हम जिन ऊंचाईयों को कृषि क्षत्रे को ले जाना चाहते हैं, मत्स्य उद्योग को ले जाना चाहते हैं आप ज़रूर ले जाएंगे। आप बहुत गहराई से चिंतन कीजिये, मौलिक विचारों का योगदान दीजिये, रोडमैप बनाइये, और मुझे पक्का विश्वास है ये वेबिनार एक साल के लिए पूरा रोडमैप तैयार करने में सफल होगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद!

31/10/2023, 15:30 Press Information Bureau

DS/TS

(रिलीज़ आईडी: 1901944) आगंतुक पटल : 384

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: Marathi , English , Urdu , Assamese , Bengali , Manipuri , Punjabi , Gujarati , Odia , Kannada , Malayalam





कर्नाटक के बेलागवी में कई विकास पहलों के शुभारंभ और पीएम-किसान की 13वीं किस्त जारी करने के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 27 FEB 2023 8:25PM by PIB Delhi

भारत माता की जय।

भारत माता की जय।

नम्मा, सबका साथ सबका विकास मंत्रदा, स्फूर्तियादा, भगवान बसवेश्वर, अविरगे, नमस्कारागळु। बेलगावियाकुंदा, मत्तुबेलगावियाजनाराप्रीती, एरडू, मिरयलागदासिहि, बेलगाविया, नन्नाबंधुभिगनियरिगे, नमस्कारागळु।

बेलगावी की जनता का प्यार और आशीर्वाद अतुलनीय है। यह प्यार, यह आशीर्वाद पाकर, हम सबको आपकी सेवा के लिए हमें दिन-रात मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। आपका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणाशक्ति बन जाता है। बेलगावी की धरती पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं होता। यह कित्तूरकीरानीचेन्नमा और क्रान्तिवीर संगोल्लीरायण्णा की भूमि है। देश आज भी इन्हें वीरता और गुलामी के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए याद करता है।

साथियों, आज़ादी की लड़ाई हो, या फिर उसके बाद भारत का नविनर्माण, बेलगावी की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है। आजकल हमारे देश में, कर्नाटका में स्टार्टअप्स की खूब चर्चा होती है। लेकिन एक तरह से देखें तो बेलगावी में तो 100 साल पहले ही स्टार्टअप्स की शुरुआत हो गई थी। 100 साल पहले। मैं आपको याद कराने आया हूं। बाबूराव पुसालकर जी ने यहां 100 साल पहले यहां एक छोटी सी यूनिट स्थापित की थी। तब से बेलगावी अनेक तरह की इंडस्ट्रीज के लिए, इतना बड़ा बेस बन गया है। बेलगावी की इसी भूमिका ने डबल इंजन सरकार इस दशक में और सशक्त करना चाहती है।

भाइयों और बहनों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे बेलगावी के विकास में नई गति आएगी। सैकड़ों करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, पानी की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप सभी को इन सारी विकास की योजनाओं के लिए इस क्षेत्र की प्रगति का एक मजबूत गति देने के इस अवसर पर मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

आज बेलगावी से पूरे हिन्दुस्तान को भी स्वागत मिली है। हिन्दुस्तान के हर किसानों को आज कर्नाटका से जोड़ा है, बेलगावी से जोड़ा है। आज यहां से पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किश्त भेजी गई है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16 हज़ार करोड़ रुपए पहुंचे हैं।

यहां जो मेरे राइतु बंधू है न, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। दुनिया के लोगों को भी अजूबा होता है। और इतनी बड़ी रकम 16 हजार करोड़ रुपया पलभर में और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई corruption नहीं, सीधा-सीधा किसान के खाते में। अगर कांग्रेस का राज होता तो प्रधानमंत्री कहते थे कांग्रेस के कि एक रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। अगर आज उन्होंने 16 हजार करोड़ का सोचा होता तो आप सोचिए 12-13 हजार करोड़ रुपया कहीं गायब हो गया होता। लेकिन यह मोदी की सरकार है। पाई-पाई आपकी है, आपके लिए है। मैं कर्नाटका सहित पूरे देश के किसान भाई-बहनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। होली के त्यौहार के पहले मेरे किसानों को यह होली की भी शुभकामनाएं हैं।

भाइयों और बहनों, आज का बदलता हुआ भारत हर वंचित को वरीयता देते हुए एक के बाद एक विकास के काम कर रहा है। हमारे देश में दशकों तक छोटे किसानों को भी नजरअंदाज किया गया था। भारत में 80-85 प्रतिशत छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब-करीब ढाई लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। आप बोलेंगे कितने किए हैं – ढ़ाई लाख करोड़, कितने? ढाई लाख करोड़ रुपया किसानों के बैंक खाते में जमा हुए हैं। इसमें भी 50 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे, हमारी जो माताएं-बहनें किसानी के करती हैं उनके खाते में जमा हुए हैं। ये पैसे किसानों की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन खर्चों के लिए अब उन्हें किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊं लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज दे करके रुपया नहीं लेने पड़ते।

साथियों, साल 2014 के बाद से, देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2014 में जब देश ने हमें अवसर दिया, तो भारत का कृषि बजट 25 हजार करोड़ रुपए था। इस वर्ष हमारा कृषि के लिए बजट...यह आंकड़ा याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे? जरा जोर से तो बोलिये याद रखोगे? देखिए जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए, आपने मौका दिया था तब भारत का कृषि बजट 25 हजार करोड़ रुपये था। कितना? 25 हजार करोड़, इस वक्त हमारा कृषि बजट 1 लाख 25 हज़ार करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानि पांच गुना ज्यादा बढोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंभीर है। कितनी सक्रिय है। हमने टेक्नॉलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है।

आप कल्पना कर सकते हैं, अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन ना बढ़ते, आधार ना होता, तो क्या ये संभव होता क्या? हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को, किसान क्रेडिटकार्ड से भी जोड़ रही है। कोशिश यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविधा लगातार रहे, हमेशा रहे। साथियों, इस वर्ष का बजट हमारी खेती की आज की स्थिति के साथ-साथ, भविष्य की ज़रूरतों को भी एड़ेस करता है।

आज की ज़रुरत भंडारण की है, स्टोरेज की है, कृषि में आने वाली लागत को कम करने की है, छोटे किसानों को संगठित करने की है। इसलिए बजट में सैकड़ों नई भंडारण सुविधाएं बनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ-साथ सहकारिता के विस्तार पर अभूतपूर्व फोकस किया है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है। नैचुरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कीटनाशक बनाने में आती है। अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हज़ारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। किसान की लागत बढ़ाने में कैमिकल फर्टिलाइजर की भूमिका अधिक होती है। अब हमने पीएम-प्रणाम योजना शुरु की है। इसके माध्यम से कैमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम, देश की कृषि को, भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इसमें नये प्राण लाने के लिए हम कृतनिश्चियी हैं बल दे रहे हैं।

क्लाइमेट चैंज के कारण कितनी समस्या आ रही है, ये हमारा किसान आज अनुभव कर रहा है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परम्पराओं की ताकत को फिर याद करना होगा। हमारा मोटा अनाज और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुंदरता भी कितनी अच्छी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है और ये superfood है। मोटा अनाज superfood है, यह अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री-अन्न के रूप में नई पहचान दी है। और कर्नाटका तो श्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और सशक्त केंद्र है। यहां तो श्री-अन्न को पहले से ही सिरी-धान्य कहा जाता है। अनेक प्रकार के श्री-अन्न यहां का किसान उगाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है।

मुझे याद है कि रइता बंधू येदियुरप्पाजी ने श्री-अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए यहां कितना बड़ा अभियान चलाया था। अब हमें इस श्री-अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। श्री-अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है। इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है।

साथियों, इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार खूब होती है। भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपिर रखा है। इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। शुगर कोऑपरेटिव द्वारा 2016-17 के पहले किए गए पेमेंट पर, टैक्स में छूट दी गई है। इससे शुगर कोऑपरेटिव को 10 हजार करोड़ रुपए का बोझ था, जो यूपीए सरकार उनके सिर पर डालकर गई थी। उन 10 हजार करोड़ रुपये का फायदा यह मेरी शुगर कोऑपरेटिव्स को होने वाला है।

आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर डेढ़ प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। जितना ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा।

भाइयों और बहनों, खेती हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, बेहतर शिक्षा हो, ये सब कुछ अच्छी कनेक्टिविटी से, और सशक्त होते हैं। इसलिए बीते वर्षों में हम कर्नाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। 2014 से पहले के 5 वर्षों में कर्नाटका में रेलवे का बजट कुल मिलाकर 4 हजार करोड़ रुपए था। जबिक इस वर्ष कर्नाटका में रेलवे के लिए, साढ़े 7 हज़ार करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस वक्त कर्नाटका में रेलवे के लगभग 45 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेट्स पर काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इसके कारण कर्नाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है।

बेलगावी का आधुनिक रेलवे स्टेशन देखकर हर किसी को आश्चर्य भी होता है, हर किसी को गर्व भी होता है। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन से यहां सुविधाएं तो अधिक हुई ही हैं, रेलवे को लेकर विश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे शानदार स्टेशन, पहले लोग, विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। कर्नाटका के अनेक स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का ऐसे ही आधुनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है। लोंडा-घाटप्रभा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज़ होगा और सुरक्षित होगा। इसी प्रकार जिन नई रेललाइनों पर आज काम शुरु हुआ है, वे भी इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क को सशक्त करेंगी। बेलगावी तो एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म के लिहाज़ से एक बड़ा सेंटर है। ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से, इन सेक्टर्स को भी लाभ होगा।

भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार, तेज़ विकास की गारंटी है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है, इसका उदाहरण जल जीवन मिशन है। साल 2019 तक कर्नाटका के गांवों में सिर्फ 25 प्रतिशत परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था। आज कर्नाटका में नल से जल की कवरेज डबल इंजन सरकार के कारण हमारे मुख्यमंत्री जी के सिक्रय प्रयासों के कारण आज कवरेज 60 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यहां बेलगावी के भी 2 लाख से भी कम घरों में नल से जल आता था। आज ये संख्या साढ़े 4 लाख पार कर चुकी है। हमारी गांव की बहनों को पानी के लिए भटकना ना पड़े, सिर्फ इसी के लिए ही इस बजट में 60 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए हैं।

भाइयों और बहनों, बीजेपी सरकार समाज के हर उस छोटे से छोटे वर्ग को सशक्त करने में जुटी है, जिसकी पहले की सरकारों ने सुध नहीं ली थी। बेलगावी तो कारीगरों, हस्तशिल्पियों, का शहर रहा है। ये तो वेनुग्राम यानि बांस के गांव के रूपमें मशहूर रहा है। आप याद कीजिए, पहले की सरकारों ने लंबे समय तक बांस की कटाई पर रोक लगा रखी। हमने कानून बदला और बांस की खेती और व्यापार के रास्ते खोल दिए। इसका बहुत बड़ा लाभ बांस का काम करने वाले कलाकारों को हुआ है। बांस के अलावा यहां दूसरे क्राफ्ट का काम भी खूब होता है। इस वर्ष के बजट में पहली बार, ऐसे साथियों के लिए, हम पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं। इस योजना से ऐसे सभी साथियों को हर प्रकार की मदद दी जाएगी।

साथियों, आज जब मैं बेलागावी आया हूं, तो एक और विषय पर अपनी बात रखना जरूर चाहूंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस किस तरह कर्नाटका से नफरत करती है। कर्नाटका के नेताओं का अपमान, कांग्रेस की पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। जिस किसी से भी कांग्रेस के परिवार विशेष को दिक्कत होने लगती है, उसकी कांग्रेस में बेइज्जती शुरू कर दी जाती है।

इतिहास गवाह है कि कैसे कांग्रेस परिवार के आगे एस. निजलिंगप्या और वीरेंद्रपाटिल जी जैसे नेताओं का अपमान कैसा किया गया था हर कर्नाटक के लोग जानते हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस के एक विशेष परिवार के आगे, कर्नाटका के एक और नेता का अपमान किया गया है। साथियों, इस धरती के संतान 50 वर्ष जिसका संसदीय कार्यकाल रहा है, ऐसे श्रीमान मिल्लिकार्जुनखड़गे जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने जनता की सेवा में अपने से जो कुछ भी हुआ करने का प्रयास किया है। लेकिन उस दिन मैं ये देखकर दुखी हो गया, जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था, छत्तीसगढ़ में उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे। और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना स्वाभाविक था। लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस की सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर, कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी को नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था।

यह बताता है कि कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है, वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोटकंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी शिकंजे में परिवारवाद के इसी शिकंजे में परिवारवाद के इसी शिकंजे में अज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटका के लोगों को भी सतर्क रहना है। और यह कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं अब तो वो सोचते जब

तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं – मर जा मोदी, मर जा मोदी। नारे बोल रहे हैं – मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में busy हो गए हैं। वो कह रहे हैं – मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है कि 'मोदी तेरा कमल खिलेगा'।

साथियों, जब सच्ची नीयत के साथ काम होता है, तब सही विकास होता है। डबल इंजन सरकार की नीयत भी सच्ची है और विकास की निष्ठा भी पक्की है। इसलिए, हमें इस विश्वास को बनाए रखना है। कर्नाटका के, देश के विकास को गति देने के लिए, हमें यूंही आगे बढ़ना है। सबका प्रयास से ही हम देश को विकसित बनाने के सपने को पूरा कर पाएंगे। और मैं आज यहां कार्यक्रम में थोड़ा देर से पहुंचा। हेलीकॉप्टर से पूरे रास्ते भर बेलगावी ने जो स्वागत किया है, जो आशीर्वाद दिए हैं। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे अभुतपूर्व दृश्य था।

में बेलगावी के कर्नाटका के इस प्यार के लिए सिर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, सिर झुका करके उनका धन्यवाद करता हूं। आज की मेरी कर्नाटका की यात्रा भी विशेष है क्योंकि आज सुबह में शिवमोगा में था और वहां पर एयरपोर्ट, कर्नाटका की जनता से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन साथ-साथ हमारे विरष्ठ नेता येदियुरप्पा जी की जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का भी मौका मिला। और शिवमोगा से यहां आया तो आप सबने को कमाल ही कर दिया। यह प्यार, यह आशीर्वाद, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बेलगावी के मेरे प्यारे भाईयों-बहनों, कर्नाटका के मेरे प्यारे भाईयों-बहनों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यह आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं न, आप जो हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं न मैं इसे ब्याज समेत लौटाऊंगा। और कर्नाटका का विकास करके लौटाऊंगा, बेलगावी का विकास करके लौटाऊंगा। फिर आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए – भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

DS/VJ/TK

(रिलीज़ आईडी: 1902882) आगंतुक पटल : 185

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Bengali , Manipuri , Assamese , Punjabi , Gujarati , Tamil , Kannada





नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस (श्री अन्न) के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

प्रविष्टि तिथि: 18 MAR 2023 2:38PM by PIB Delhi

आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नरेन्द्र तोमर जी, मनसुख मंडाविया जी, पीयूष गोएल जी, श्री कैलाश चौधरी जी! विदेशों से आए हुए कुछ मंत्रिगण गुयाना, मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम और गाम्बिया के सभी माननीय मंत्रिगण, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विभिन्न FPO's और Starts-Ups के युवा साथी, देश के कोने-कोने से जुड़े लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों,

आप सभी को 'ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस' के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। इस तरह के आयोजन न केवल Global Good के लिए जरूरी हैं, बल्कि Global Good में भारत की बढ़ती ज़िम्मेदारी का भी प्रतीक हैं।

साथियों,

आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को 'इंटरनेशनल मिलेट इयर' घोषित किया है। जब हम किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं, तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि, आज विश्व जब 'इंटरनेशनल मिलेट इयर' मना रहा है, तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। 'ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस' इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुडी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केन्द्र, स्कूल-कॉलेज और एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे साथ शामिल हैं। Indian Embassies से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारोह में मौजूद हैं। ये भी इसके महात्मय को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी यहां मिलेट्स पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां Book of Millet Standards को भी लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही ICAR के 'इंडियन इंस्टीट्यट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, को Global Centre of Excellence घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था, मैं आप सबसे भी और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हों उनसे भी आग्रह करुंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दिनया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए सभी पहुलओं को समझने के लिए से एग्जीबिशन देखना, मैं आप सबको आग्रह करूंगा जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए-नए स्टार्टअप्स लेकर के इस फिल्ड में आए हैं ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी. भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

Friends,

ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को, लाखों किसानों के सामने मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए, भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को, अब श्रीअन्न की पहचान दी गई है। श्रीअन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित हैं, वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ किसी के आगे 'श्री' ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है, वहाँ समृद्धि भी होती है, और समग्रता भी होती है। श्रीअन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गाँव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्रीअन्न यानि देश के

छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार, श्रीअन्न यानि देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार, श्रीअन्न यानि देश के आदिवासी समाज का सत्कार, श्रीअन्न यानि कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार, श्रीअन्न यानि केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार, श्रीअन्न यानि Climate Change की चुनौती से निपटने में मददगार।

साथियों.

हमने श्रीअन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को nutri-cereals के तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाज़ार में interest पैदा करने तक, हर स्तर पर काम किया गया। हमारे यहाँ 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है। लेकिन, इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति, प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है। यानि दो तीन किलो से बढ़कर के 14 किलो। मिलेट्स फूड प्रॉडक्ट्स की बिक्री भी करीब 30 प्रतिशत बढ़ी है। अब जगह-जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं, मिलेट्स से जुड़ी रेसीपीज के सोशल मीडिया चैनल्स बन रहे हैं। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट' स्कीम के तहत भी select किया गया है।

साथियों.

हम जानते हैं कि, श्रीअन्न उगाने वाले ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं, Marginal Farmers हैं। और कुछ लोग ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब-करीब ढाई करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम जमीन है, और इन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन, श्रीअन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान, देश के ढाई करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार, मिलेट्स पैदा करने वाले ढाई करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट्स-श्रीअन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन ढाई करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। Processed और packaged food items के जिरए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुँच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्रीअन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी बने हैं। बड़ी संख्या में FPOs इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जिरए मिलेट्स के उत्पाद बना रहीं हैं। गाँव से निकलकर ये प्रॉडक्ट्स मॉल और सुपरमार्केट्स तक पहुँच रहे हैं। यानी, देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है, और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है।

साथियों.

भारत इस समय जी-20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है- One Earth, One Family, One Future पूरे विश्व को

एक परिवार मानने की ये भावना, इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है। विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प, सदैव भारत के मन में रहा है। आप देखिए,जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिरए पूरे विश्व को उसका लाभ मिले। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देश आयुर्वेद को भी मान्यता दे चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर एलायंस के रूप में आज भारत का ये प्रयास sustainable planet के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है। और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि ISA से भी 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। आज चाहे LiFE मिशन की अगुवाई हो, Climate Change से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करना हो, हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हैं, समाज में बदलाव को शुरू करते हैं, और उसे विश्व कल्याण की भावना तक लेकर जाते हैं। और यही आज भारत के 'मिलेट मूवमेंट' में भी दिख रहा है। श्रीअन्न सदियों से भारत में जीवनशैली का हिस्सा रहा है। अलग-अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगी, चीना, कोदों, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्रीअन्न भारत में प्रचलन में हैं। हम श्रीअन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धितयों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। इसलिए, जिन मित्र देशों के एप्रीकल्चर मिनिस्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक stable mechanism develop करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर, फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक, एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, ये हम सबकी साझा जिमोदारी है।

साथियों.

आज इस मंच पर मैं, मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की ये ताकत है- इसका climate resilient होना। बहुत Adverse Climatic Conditions में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वॉटर crisis वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी ये है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी, मिलेट्स, मानव और मिट्टी, दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देते हैं।

साथियों.

जब हम फूड security की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है, जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जहां फूड हैबिट्स से जुड़ी बीमारियाँ एक बड़ी समस्या बनती जा रही हैं। यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी, एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या, तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी! दोनों ही जगहों पर, इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन श्रीअन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है। इसमें खर्च भी बहुत कम होता है, और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्रीअन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह हैं। इसी तरह, श्रीअन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाइ फ़ाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल related बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी, पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक, हमारी कई समस्याओं के हल हमें श्रीअन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं।

साथियों.

मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्रीअन्न का योगदान केवल 5-6 प्रतिशत है। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए achievable targets सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए PLI स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियाँ मिलेट प्रॉडक्ट्स बनाने के लिए आगे आयें, इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना होगा। कई राज्यों ने अपने यहाँ PDS सिस्टम में श्री अन्न को शामिल किया है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। मिड डे मील में भी श्रीअन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, खाने में नया स्वाद और विविधता जोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है, इन सभी बिन्दुओं पर इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा होगी, और उन्हें implement करने का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। हमारे अन्तदाता के, और हम सबके साझा प्रयासों से श्रीअन्न भारत की और विश्व की समृद्धि में नई चमक जोड़ेगा। इसी कामना के साथ, आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे दोनो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने समय निकालकर के हमें जो संदेश भेजा उन दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद!

DS/SH/DK

(रिलीज़ आईडी: 1908335) आगंतुक पटल : 473

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Manipuri , Bengali , Assamese , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam

31/10/2023, 15:57 Press Information Bureau





प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित की

1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र समर्पित किए पीएम-किसान के अंतर्गत लगभग 17,000 करोड़ रुपये की 14वीं किस्त राशि जारी की

डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) पर 1600 किसान उत्पादक संगठनों को शामिल किया

यूरिया गोल्ड- सल्फर लेपित यूरिया लॉन्च

5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन और 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी

"केंद्र की सरकार किसानों की पीड़ा और आवश्यकताओं को समझती है"

"सरकार यूरिया के मूल्यों से किसानों को परेशान नहीं होने देगी। जब कोई किसान यूरिया खरीदने जाता है, तो उसे विश्वास होता है कि मोदी की गारंटी है"

"भारत केवल विकसित गांवों के साथ ही विकसित हो सकता है"
"राजस्थान में आधुनिक अवसंरचना निर्माण करना हमारी प्राथिमकता है"
"हम सब मिलकर राजस्थान के गौरव और विरासत को पूरे विश्व में एक नई पहचान देंगे"

प्रविष्टि तिथि: 27 JUL 2023 1:03PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) को राष्ट्र को समर्पित करना, सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च करना, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क

(ओएनडीसी) पर 1600 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को शामिल करना, 8.5 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत लगभग 17,000 करोड़ रुपये की 14वीं किस्त राशि जारी करना, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, बारां, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास और उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालय तिंवरी, जोधपुर का उद्घाटन शामिल है।

प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पीएम किसान समृद्धि केंद्र के मॉडल को देखा। प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए देश के विभिन्न स्थानों से आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले करोड़ों किसानों के प्रति सम्मान व्यक्त किया और कहा कि खाटू श्याम जी की भूमि भारत के कोने-कोने से आने वाले तीर्थयात्रियों को आश्वस्त करती है। उन्होंने शेखावाटी की वीर भूमि से विभिन्न विकास कार्यक्रमों की शुरुआत करने का अवसर मिलने पर आभार व्यक्त किया और करोड़ों किसान-लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत किस्त सीधे हस्तांतिरत करने का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने देश में 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को समर्पित करने बारे में कहा कि इससे गांव और ब्लॉक स्तर पर करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। उन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के जुड़ने का भी उल्लेख किया और कहा कि इससे किसानों के लिए देश के किसी भी हिस्से से अपनी उपज को बाजार तक ले जाना आसान हो जाएगा। उन्होंने यूरिया गोल्ड, नए मेडिकल कॉलेजों और एकलव्य मॉडल स्कूलों के शुभारंभ का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आज की विकास परियोजनाओं के लिए भारत के लोगों के साथ-साथ करोड़ों किसानों को बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने सीकर और शेखावाटी क्षेत्रों के किसानों के महत्व को रेखांकित करते हुए क्षेत्र की किठनाइयों के बावजूद उनकी कड़ी मेहनत के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार किसानों की पीड़ा और जरूरतों को समझती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे पिछले 9 वर्षों में बीज से बाजार (बीज से बाजार तक) तक नई प्रणालियां बनाई गई हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से करोड़ों किसान मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान के आधार पर अधिकतम निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इन केंद्रों को किसानों की आवश्कताओं के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये केंद्र किसानों को कृषि से संबंधित मुद्दों पर उन्नत आधुनिक जानकारी भी प्रदान करेंगे और सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में भी समय पर जानकारी प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने किसानों को सलाह दी कि वे केंद्रों का दौरा करते रहें और वहां उपलब्ध ज्ञान का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्षांत से पहले अतिरिक्त 1.75 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के खर्चों को कम करने और जरुरत के समय उनकी सहायता करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्र करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जहां किसानों के बैंक खातों में सीधे धन हस्तांतरित किया जाता है। उन्होंने बताया कि आज की 14वीं किस्त को शामिल किया जाए तो अब तक 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है, जो विभिन्न खर्चों को कवर करने में किसानों के लिए लाभकारी रही है। उन्होंने कहा कि देश में यूरिया की कीमत सरकार द्वारा किसानों का खर्च बचाने का उदाहरण है। कोरोना वायरस महामारी और रुस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों में आई बाधा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि वर्तमान सरकार ने इसे देश के किसानों पर इसका असर नहीं पड़ने दिया। प्रधानमंत्री ने उर्वरकों की कीमतों के बारे में बताया कि यूरिया की जिस बोरी की कीमत भारत में 266 रुपये है, उसका मूल्य पाकिस्तान में लगभग 800 रुपये, बांग्लादेश में लगभग 720 रुपये, चीन में लगभग 2100 रुपये और अमेरिका में लगभग 3000 रुपये है। "सरकार हमारे किसानों को यूरिया की कीमतों से परेशान नहीं होने देगी", श्री मोदी ने कहा, "जब कोई किसान युरिया खरीदने जाता है, तो उसे विश्वास होता है कि यह मोदी की गारंटी है।

प्रधानमंत्री ने मोटे अनाजों को बढ़ावा देने और उनकी ब्रांडिंग श्री अन्न के रूप में करने जैसे उपायों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि श्री अन्न के प्रचार-प्रसार के माध्यम से इसके उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात में वृद्धि हो रही है। उन्होंने अपनी हील की यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के आधिकारिक रात्रिभोज में मोटे अनाज की उपस्थिति को याद किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ''भारत का विकास तभी संभव है जब उसके गांवों का विकास हो। विकसित गांवों के साथ ही भारत विकसित हो सकता है। यही कारण है कि सरकार गांवों में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है, जो अब तक केवल शहरों में उपलब्ध थीं। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य अवसंरचना के विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान में 9 वर्ष पहले तक केवल दस मेडिकल कॉलेज थे। आज यह संख्या 35 तक पहुंच गई है। इससे आस-पास के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हो रहा है और मेडिकल छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जिन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया जा रहा है और जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, उनसे राज्य के कई क्षेत्रों में चिकित्सा अवसंरचना में सुधार होगा। जैसा कि चिकित्सा शिक्षा को सुलभ बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में मेडिकल शिक्षा प्रदान करने, इसे और लोकतांत्रिक बनाने और वंचित वर्गों के लिए रास्ते खोलने के कदम का भी उल्लेख किया। अब किसी गरीब का बेटा या बेटी अंग्रेजी न जानने के कारण डॉक्टर बनने के अवसर से वंचित नहीं रहेगा। यह भी मोदी की गारंटी है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों तक गांवों में अच्छे स्कूलों और शिक्षा की कमी के कारण गांव और गरीब भी पीछे छूट गए थे और अफसोस जताया कि पिछड़े और जनजातीय समाज के बच्चों के पास अपने सपनों को पूरा करने का कोई साधन नहीं था। श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने शिक्षा के लिए बजट और संसाधनों में वृद्धि की है और एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले हैं, जिससे जनजातीय युवाओं को काफी लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सफलता तभी बड़ी होती है जब सपने बड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसके वैभव ने सिदयों से दुनिया को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को आधुनिक विकास की ऊंचाई पर ले जाते हुए भूमि की विरासत को संरक्षित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही कारण है कि राजस्थान में आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने पिछले कुछ महीनों में दो हाईटेक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का उल्लेख किया और कहा कि राजस्थान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे के एक प्रमुख खंड के माध्यम से विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने राज्य से चलाई जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार अवसंरचना में निवेश कर रही है और पर्यटन से संबंधित सुविधाओं का विकास कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा, "जब राजस्थान 'पधारो म्हारे देश' का आह्वान करेगा तो एक्सप्रेसवे और बेहतर रेल सुविधाएं पर्यटकों का स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री ने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत खाटू श्याम जी मंदिर में सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया और विश्वास व्यक्त किया कि श्री खाटू श्याम के आशीर्वाद से राजस्थान के विकास को और गित मिलेगी। हम सब मिलकर राजस्थान के गौरव और विरासत को पूरे विश्व में एक नई पहचान देंगे।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। श्री अशोक गहलोत पिछले कुछ समय से बीमार हैं और इस कार्यक्रम में नहीं आ सके।

इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मांडविया, केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे।

पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री ने किसानों को लाभान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) राष्ट्र को समर्पित किए। सभी किसानों की जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए पीएमकेएसके विकसित किए जा रहे हैं। कृषि इनपुट (उर्वरकों, बीजों, उपकरणों) की जानकारी से लेकर मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाओं तक, विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी तक, पीएमकेएसके को देश में किसानों के लिए एक विश्वसनीय समर्थन प्रणाली बनाने की परिकल्पना की गई है। वे ब्लॉक/जिला स्तर के विक्रय केंद्रों पर उर्वरक खुदरा विक्रेताओं का नियमित क्षमता निर्माण भी सुनिश्चित करेंगे।

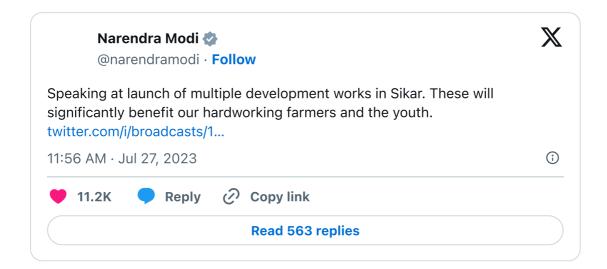
प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड की एक नई किस्म का शुभारंभ किया, जो सल्फर के साथ लेपित है। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करेगी। यह अभिनव उर्वरक नीम-लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और कुशल है, पौधों में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में सुधार करता है, उर्वरक की खपत को कम करता है, और फसल की गुणवत्ता को बढाता है।

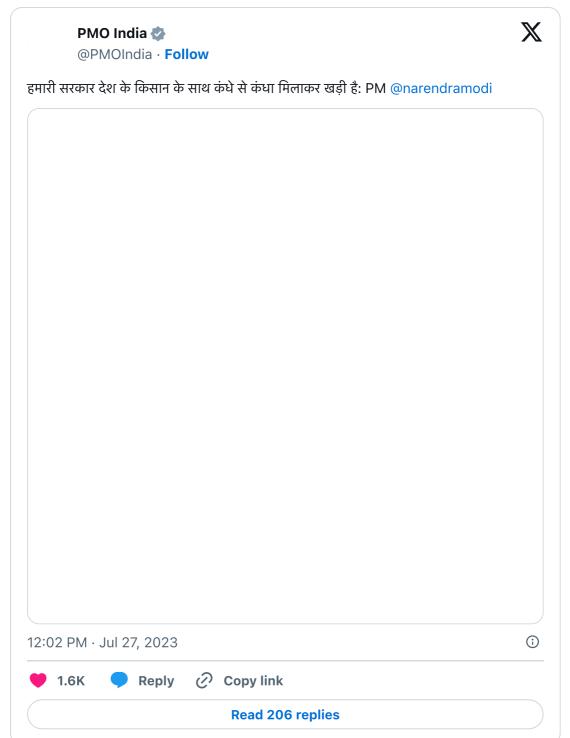
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) से 1600 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को जोड़ने की शुरुआत की। ओएनडीसी एफपीओ को डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस-टू-कंज्यूमर लेनदेन तक सीधी पहुंच के साथ सशक्त बनाता है, और स्थानीय मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स के विकास को उत्प्रेरित करता है।

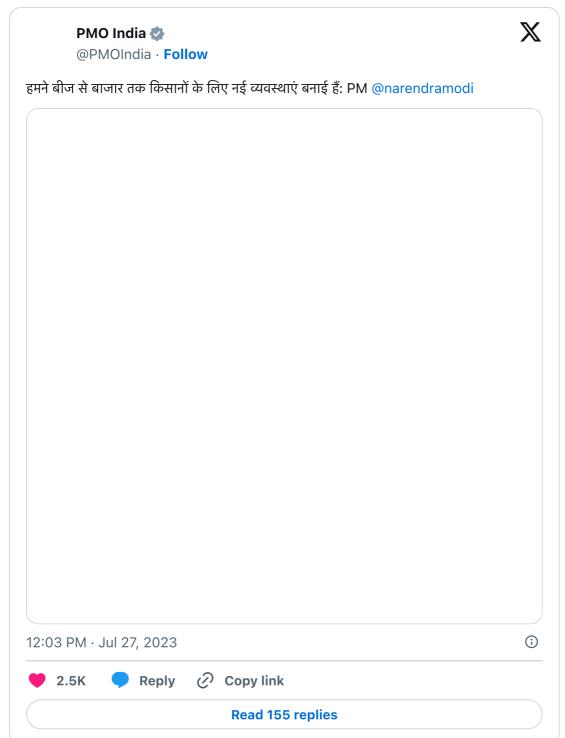
किसानों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण पेश करने वाले एक कदम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत लगभग 17,000 करोड़ रुपये की 14वीं किस्त की राशि 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी की गई।

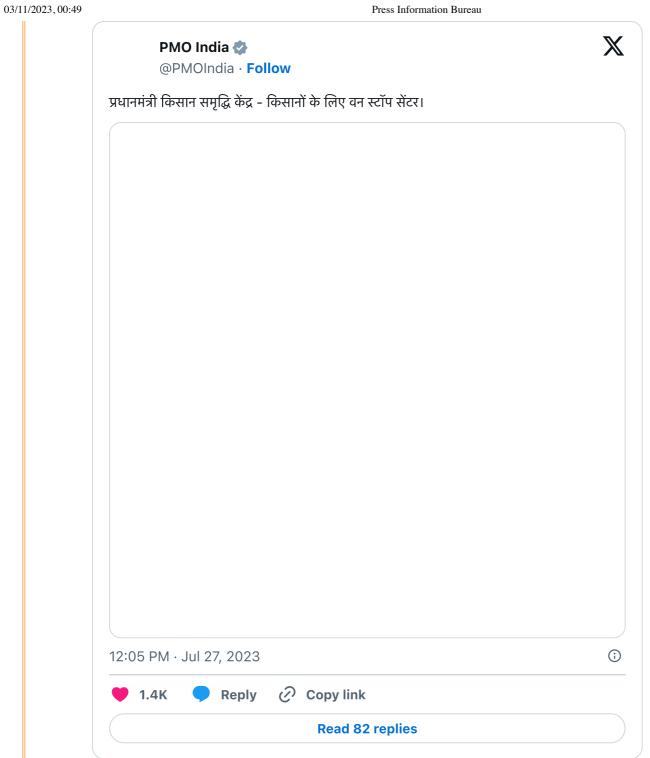
प्रधानमंत्री ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में पांच नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और बारां, बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में सात मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत की जा रही है। प्रधानमंत्री ने जिन पांच मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है, उन्हें 1400 करोड़ रुपये से अधिक की संचयी लागत से विकसित किया गया है, जबिक जिन सात मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी वे 2275 करोड़ रुपये की संचयी लागत से बनाए जाएंगे। 2014 तक राजस्थान में केवल 10 मेडिकल कॉलेज थे। केंद्र सरकार के समर्पित प्रयासों के माध्यम से राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 35 हो गई है। यह 250 प्रतिशत की वृद्धि है। इन 12 नए मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2013-14 में 1750 सीटों से बढ़कर 6275 हो जाएगी, जो 258 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

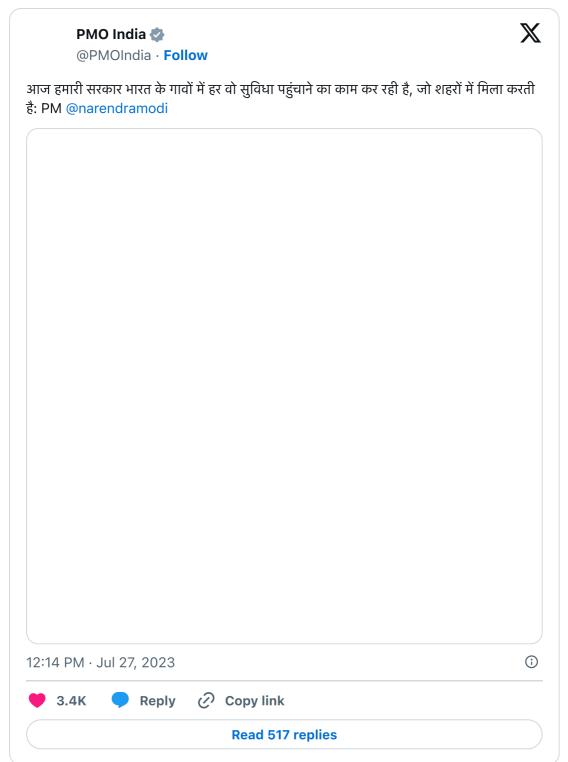
प्रधानमंत्री ने इसके अतिरिक्त उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में छह एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया, जिससे इन जिलों में रहने वाली जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी। वह कार्यक्रम के दौरान जोधपुर में केंद्रीय विद्यालय, तिंवरी का भी उद्घाटन किया।













PM Modi lays foundation stone/inaugurates/dedicates various Projects a



एमजी/एमएस/आरपी/एजी/एनजे/एसके

(रिलीज़ आईडी: 1943230) आगंतुक पटल : 453

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Nepali , Marathi , Manipuri , Bengali , Punjabi , Gujarati , Odia , Tamil , Telugu , Kannada , Malayalam